

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2010—फाल्गुन 21, शक 1931

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2010

क्र. ई-5-326-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. सिंघई,  
आय.ए.एस. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख  
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा  
20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2010  
तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा इस  
अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक  
अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री डी. सिंघई की अवकाश की अवधि में श्री ए. पी.  
श्रीवास्तव, आय.ए.एस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक

कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप  
से आगामी आदेश तक सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन  
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सिंघई को अस्थायी रूप से  
आगामी आदेश तक स्थानापन्न सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग  
एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं  
सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के पद पर पुनः  
पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. सिंघई द्वारा सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं  
पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी  
विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने  
पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं

पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अविनि वैश्य, मुख्य सचिव.

### खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2010

क्र. एफ-5-23-2009-उन्तीस (2).—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री लखनलाल शुक्ला को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतियोगिता फोरम, रीवा में सदस्य के रूप में की गई नियुक्ति संबंधी समसंख्यक आदेश दिनांक 20/24 जुलाई 2009, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. जैन, अपर सचिव.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त, पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार, उक्त सारणी के कालम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करता है, अर्थात्:—

#### सारणी

अनु- क्रमांक	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/ सत्र खण्ड
(1)	(2)	(3)
1.	विशेष न्यायालय, अलीराजपुर	अलीराजपुर

(1)	(2)	(3)
2.	विशेष न्यायालय, अनूपपुर	अनूपपुर
3.	विशेष न्यायालय, अशोकनगर	अशोकनगर
4.	विशेष न्यायालय, बालाघाट	बालाघाट
5.	विशेष न्यायालय, बड़वानी	बड़वानी
6.	विशेष न्यायालय, बैतूल	बैतूल
7.	विशेष न्यायालय, भिण्ड	भिण्ड
8.	विशेष न्यायालय, भोपाल	भोपाल
9.	विशेष न्यायालय, बुरहानपुर	बुरहानपुर
10.	विशेष न्यायालय, छतरपुर	छतरपुर
11.	विशेष न्यायालय, छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
12.	विशेष न्यायालय, दमोह	दमोह
13.	विशेष न्यायालय, दतिया	दतिया
14.	विशेष न्यायालय, देवास	देवास
15.	विशेष न्यायालय, धार	धार
16.	विशेष न्यायालय, डिण्डौरी	डिण्डौरी
17.	विशेष न्यायालय, पूर्व निमाड़ खण्डवा	पूर्व निमाड़ खण्डवा
18.	विशेष न्यायालय, गुना	गुना
19.	विशेष न्यायालय, ग्वालियर	ग्वालियर
20.	विशेष न्यायालय, हरदा	हरदा
21.	विशेष न्यायालय, होशंगाबाद	होशंगाबाद
22.	विशेष न्यायालय, इन्दौर	इन्दौर
23.	विशेष न्यायालय, जबलपुर	जबलपुर
24.	विशेष न्यायालय, झाबुआ	झाबुआ
25.	विशेष न्यायालय, कटनी	कटनी
26.	विशेष न्यायालय, मण्डला	मण्डला
27.	विशेष न्यायालय, मन्दसौर	मंदसौर सत्र खण्ड, अतिरिक्त विशेष न्यायालय, मन्दसौर तथा अतिरिक्त विशेष न्यायालय, गरोठ को दिए गए क्षेत्राधिकार को छोड़कर.
28.	अतिरिक्त विशेष न्यायालय, मन्दसौर	तहसील मल्हारगढ़ तथा सीतामऊ के स्थानीय क्षेत्र.
29.	अतिरिक्त विशेष न्यायालय, गरोठ	गरोठ तथा भानपुरा के स्थानीय क्षेत्र.
30.	विशेष न्यायालय, मुरैना	मुरैना

(1)	(2)	(3)
31.	विशेष न्यायालय, नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
32.	विशेष न्यायालय, नीमच	नीमच
33.	विशेष न्यायालय, पन्ना	पन्ना
34.	विशेष न्यायालय, रायसेन	रायसेन
35.	विशेष न्यायालय, राजगढ़	राजगढ़
36.	विशेष न्यायालय, रतलाम	रतलाम सत्र खण्ड, अतिरिक्त विशेष न्यायालय, जावरा को दिये गये क्षेत्राधिकार को छोड़कर.
37.	अतिरिक्त विशेष न्यायालय, जावरा	पुलिस थाना जावरा, शहर, औद्योगिक क्षेत्र जावरा, कालूखेड़ा, रिगनौद, बड़वदा, पिपलौदा तथा पुलिस थाना ताल का स्थानीय क्षेत्र.
38.	विशेष न्यायालय, रीवा	रीवा
39.	विशेष न्यायालय, सागर	सागर
40.	विशेष न्यायालय, सतना	सतना
41.	विशेष न्यायालय, सीहोर	सीहोर
42.	विशेष न्यायालय, सिवनी	सिवनी
43.	विशेष न्यायालय, शहडोल	शहडोल
44.	विशेष न्यायालय, शाजापुर	शाजापुर
45.	विशेष न्यायालय, श्योपुर	श्योपुर
46.	विशेष न्यायालय, शिवपुरी	शिवपुरी
47.	विशेष न्यायालय, सीधी	सीधी सत्र खण्ड, विशेष न्यायालय, बैदन को दिये गये क्षेत्राधिकार को छोड़कर.
48.	विशेष न्यायालय, बैदन	बैदन (राजस्व जिला, सिंगरोली मुख्यालय बैदन की स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारिता में उद्भूत तथा संबंधित मामले)
49.	विशेष न्यायालय, टीकमगढ़	टीकमगढ़
50.	विशेष न्यायालय, उज्जैन	उज्जैन

(1)	(2)	(3)
51.	विशेष न्यायालय, उमरिया	उमरिया
52.	विशेष न्यायालय, विदिशा	विदिशा
53.	विशेष न्यायालय, पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.

**टिप्पणी.**—सेशन न्यायाधीश किसी विशेष न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, इस अधिसूचना के अधीन विशेष न्यायाधीशों के बीच अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु व्यवस्था कर सकेंगे.

F.No. 1-6-89-XXI-B(I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government with the concurrence of Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby constitutes Special Courts as specified in column (2) of the Table below for the area specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table:—

TABLE

S.No.	Special Court	Local area/ Sessions Divisions
(1)	(2)	(3)
1.	Special Court, Alirajpur	Alirajpur
2.	Special Court, Anuppur	Anuppur
3.	Special Court, Ashoknagar	Ashoknagar
4.	Special Court, Balaghat	Balaghat
5.	Special Court, Barwani	Barwani
6.	Special Court, Belul	Belul
7.	Special Court, Bhind	Bhind
8.	Special Court, Bhopal	Bhopal
9.	Special Court, Burhanpur	Burhanpur
10.	Special Court, Chhatarpur	Chhatarpur
11.	Special Court, Chhindwara	Chhindwara
12.	Special Court, Damoh	Damoh
13.	Special Court, Datia	Datia
14.	Special Court, Dewas	Dewas
15.	Special Court, Dhar	Dhar
16.	Special Court, Dindori	Dindori
17.	Special Court, East Nimar Khandwa.	East Nimar Khandwa.
18.	Special Court, Guna	Guna
19.	Special Court, Gwalior	Gwalior
20.	Special Court, Harda	Harda

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
21.	Special Court, Hoshangabad	Hoshangabad	45.	Special Court, Sheopur	Sheopur
22.	Special Court, Indore	Indore	46.	Special Court, Shivpuri	Shivpuri
23.	Special Court, Jabalpur	Jabalpur	47.	Special Court, Sidhi	Sidhi Sessions Division except jurisdiction given to Special Court, Waidhan.
24.	Special Court, Jhabua	Jhabua			
25.	Special Court, Katni	Katni			
26.	Special Court, Mandla	Mandla			
27.	Special Court, Mandsaur	Mandsaur Sessions Division except jurisdiction given to Additional Special Court, Mandsaur and Additional Special Court Garoth.	48.	Special Court, Waidhan	Waidhan (Cases arising out of and pertaining to local territorial jurisdiction of Revenue District, Singroli headquarters at Waidhan).
28.	Additional Special Court, Mandsaur.	Local area of Tehsil Malhargarh and Sitamau.	49.	Special Court, Tikamgarh	Tikamgarh
29.	Additional Special Court, Garoth.	Local area of Garoth and Bhanpura.	50.	Special Court, Ujjain	Ujjain
30.	Special Court, Morena	Morena	51.	Special Court, Umaria	Umaria
31.	Special Court, Narsinghpur	Narsinghpur	52.	Special Court, Vidisha	Vidisha
32.	Special Court, Neemuch	Neemuch	53.	Special Court, W. N.	W.N. Mandleswar
33.	Special Court, Panna	Panna			
34.	Special Court, Raisen	Raisen			
35.	Special Court, Rajgarh	Rajgarh			
36.	Special Court, Ratlam	Ratlam Sessions Divisions except jurisdiction given to Additional Special Court, Jaora.			
37.	Additional Special Court, Jaora.	Local area of Police Station Jaora City, Industrial area Jaora, Kalukheda, Ring Road, Badauda, Piploda and Police Station Taal.			
38.	Special Court, Rewa	Rewa			
39.	Special Court, Sagar	Sagar			
40.	Special Court, Satna	Satna			
41.	Special Court, Sehore	Sehore			
42.	Special Court, Seoni	Seoni			
43.	Special Court, Shahdol	Shahdol			
44.	Special Court, Shajapur	Shajapur			

**Note.**—The Sessions Judge may make arrangement for hearing of urgent matters amongst the Special Judges under this notification in absence of any such Special Judge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. 1(सी)-1-इक्कीस-ब (दो)-10.—राज्य शासन ने अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत गठित प्रत्येक विशेष न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की है.

2. उपरोक्त विशेष न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से सामान्य दाण्डिक मामलों का श्रवणाधिकार प्राप्त है. अतः ऐसे अभियोजित किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरणों के लिये, राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिये, उपरोक्त विशेष लोक अभियोजकों को मात्र उसी न्यायालय के लिये, पदेन अतिरिक्त लोक अभियोजक की शक्तियां धारा 24(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदान की जाती हैं, जो उन्हें उस न्यायालय के लिये, अन्य व्यवस्था होने तक प्राप्त रहेगी.

3. ऐसे विशेष लोक अभियोजकों से सामान्य दाण्डिक मामलों में पैरवी हेतु पृथक् से कोई शुल्क देय नहीं होगा. परन्तु वे अपने शुल्क के नियमित बिलों में समय की गणना करते समय सामान्य दाण्डिक मामलों में लगे समय का लाभ ले सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)-163-2006-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, श्री सतीश कुमार यादव, नोटरी निवासी पिपरिया, जिला होशंगाबाद का नोटरी अधिनियम, 1952 तथा नोटरी नियम, 1956 के सहपठित नियम 13 के अन्तर्गत नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण आदेश क्रमांक 17(ई)-72-2009-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 1 जुलाई 2009 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2009

क्र. 1-13-3251-09.—मण्डल ने मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-9-2-2009-नियम-चार (भाग-1) दिनांक 3 अगस्त 2009 जो दिनांक 1 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का समेकन (Consolidation) से संबंधित है, को यथाआवश्यक परिवर्तन (Mutatis Mutandis) सहित निम्नानुसार ग्राह्य करने का निर्णय लिया है:—

- 1.1 दिनांक 31 अगस्त 2008 की स्थिति में प्राप्त मूल पेंशन (कम्यूटेशन के पूर्व) अथवा परिवार पेंशन (मंहगाई पेंशन एवं मंहगाई राहत को छोड़कर) का 2.26 गुणा राशि, पेंशन अथवा परिवार पेंशन की समेकित राशि (Consolidated Amount) होगी तथा इसका भुगतान सितम्बर 2008 (माह सितम्बर 2008 भुगतान माह अक्टूबर, 2008) से देय होगा.
- 1.2 न्यूनतम पेंशन/परिवार पेंशन रुपये 3025/- प्रतिमाह देय होगी. वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन की राशि इस सीमा से पृथक् रहेगी.
- 1.3 वृद्ध पेंशनरों को निम्नांकित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी:—

पेंशनर/परिवार पेंशनर की उम्र	अतिरिक्त राशि
80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 20%
85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 30%
90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 40%
95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 50%
100 वर्ष या अधिक.	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 100%

अतिरिक्त पेंशन, संबंधित लेखा इकाई स्वीकृत करेंगे, इसके लिए पृथक् से प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी. अतिरिक्त पेंशन की राशि पेंशनर भुगतान आदेश में पृथक् से दर्शायी जायेगी. सेवानिवृत्ति पेंशन भोगी के पेंशन आदेश में उल्लेखित जन्मतिथि को आधार मानकर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी. परिवार पेंशनर के मामले में आयु संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी. अतिरिक्त पेंशन का लाभ, पेंशनर जिस माह निर्धारित आयु पूर्ण करेंगे उस माह के आगामी माह से प्राप्त होगा. अतिरिक्त राशि की गणना ठीक पूर्ववर्ती माह में प्राप्त मूल पेंशन के आधार पर की जाएगी, परन्तु जिन्होंने दिनांक 1 सितम्बर 2008 के पूर्व पैरा 1.3 अनुसार आयु पूर्ण कर ली है तब उन्हें पेंशन पुनरीक्षण उपरान्त सितम्बर 2008 में देय पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि का लाभ दिया जाए.

2. यदि पेंशनर/परिवार पेंशनर को एक से अधिक पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है तो न्यूनतम राशि रुपये 3025/- दोनों पेंशनों पर पृथक्-पृथक् देय होगी.

3. नियुक्त/पुनर्नियुक्त पेंशनरों के मामले में पेंशन/परिवार पेंशन का केवल समेकन होगा तथा समेकित पेंशन/ परिवार पेंशन पर राहत की पात्रता नहीं होगी.

4. पेंशन/परिवार पेंशन के समेकन फलस्वरूप प्राप्त होने वाली एरियस की राशि में से पूर्व में भुगतान की गई पेंशन/परिवार पेंशन, मण्डल के आदेश क्रमांक 1-13-3824-15, दिनांक 11 अप्रैल 2007 द्वारा स्वीकृत की गई 50 प्रतिशत मंहगाई, पेंशन, आदेश क्रमांक 1-13-3801-27, दिनांक 31 जुलाई 2008 द्वारा स्वीकृत 47 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत और मण्डल के आदेश क्रमांक 1-07-डब्ल्यू.ए.सी.-4987, दिनांक 11 सितम्बर 2008 द्वारा स्वीकृत 7.5 प्रतिशत अंतरिम राहत की राशियां समायोजित की जावेगी.

5. पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण कार्य संबंधित लेखा इकाई द्वारा किया जावेगा.

6. संबंधित लेखा इकाई परिवार पेंशन को पुनरीक्षित करते समय इस बात की भली भांति जांच कर ले कि परिवार पेंशन की बढ़ी हुई दर की तारीख निकल जाने के बाद भी यदि भुगतान बढ़ी दर से हो रहा हो तो परिवार पेंशन का भुगतान सामान्य दर से कर दें तथा अधिक भुगतान राशि को एरियर्स/राहत से समायोजित करें.

7. उपरोक्तानुसार समेकित पेंशन/परिवार पेंशन की राशि रुपयों एवं पैसों में आने पर पैसे के भाग को आगामी रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा.

8. इन निर्देशों के अन्तर्गत समेकित पेंशन/परिवार पेंशन, मूल पेंशन होगी. दिनांक 1 सितम्बर 2008 (माह सितम्बर 2008 की पेंशन जो माह अक्टूबर 2008 में देय) से मूल पेंशन पर 12 प्रतिशत की दर से तथा माह जुलाई 2009 (माह जुलाई 2009 की पेंशन जो माह अगस्त 2009 में देय) से 16 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत देय होगी. उपरोक्त पैरा 1.3 अनुसार वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी. मंहगाई राहत देने के संबंध में अन्य शर्तें पूर्व में प्रसारित मंहगाई राहत के आदेशों के अनुसार होगी.

9. पेंशन/परिवार पेंशन के समेकन के फलस्वरूप एरियर्स राशि का भुगतान 6 समान मासिक किश्तों में किया जावेगा.

क्र. 01-13-3251-11.—मण्डल ने मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-2-2009-नियम-चार (भाग-2) दिनांक 3 अगस्त 2009 जो दिनांक 1 जनवरी 2006 को या पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण से संबंधित है, को यथा आवश्यक परिवर्तन (Mutatis Mutandis) सहित निम्नानुसार ग्राह्य करने का निर्णय लिया है:—

- (1) **पेंशन.**—पेंशन का निर्धारण अंतिम माह के मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे) के आधार पर होगा. पेंशन 33 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अंतिम माह के मूलवेतन के 50% की दर से देय होगी. न्यूनतम पेंशन रुपये 3025/- प्रतिमाह होगी.
- (2) **परिवार पेंशन.**—अंतिम मूलवेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे) के 30% की दर से देय होगी. न्यूनतम पेंशन रुपये 3025/- प्रतिमाह होगी. वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन की राशि इस सीमा से पृथक् रहेगी.
- (3) **अतिरिक्त पेंशन.**—वृद्ध पेंशनरों को निम्नांकित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी:—

पेंशनर/परिवार पेंशनर की उम्र	अतिरिक्त राशि
80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 20%

पेंशनर/परिवार पेंशनर की उम्र	अतिरिक्त राशि
85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 30%
90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 40%
95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 50%
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 100%

अतिरिक्त पेंशन, संबंधित लेखा इकाई द्वारा स्वीकृत की जायेगी. इसके लिए पृथक्से प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी. अतिरिक्त पेंशन की राशि पेंशनर भुगतान आदेश में पृथक् से दर्शायी जायेगी. सेवानिवृत्त पेंशन भोगी के पेंशन आदेश में उल्लेखित जन्मतिथि के आधार पर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी. परिवार पेंशन भोगी के मामले में आयु संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी. अतिरिक्त पेंशन का लाभ, पेंशनर जिस माह निर्धारित आयु पूर्ण करेंगे उस माह के आगामी माह से देय होगी.

(4) दिनांक 31 अगस्त 2008 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन परिलब्धियों का निर्धारण निम्नानुसार होगा:—

(क) **मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी)** की अधिकतम राशि रुपये 3.50 लाख को बढ़ाकर 1 सितम्बर 2008 से रुपये 10.00 लाख (दस लाख) किया जाता है. ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण करने के लिए अंतिम माह का मूलवेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे) तथा इस पर देय मंहगाई भत्ता गणना में लिया जायेगा. 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर 16½ (साढ़े सोलह) माह की उपलब्धियां अथवा राशि रुपये 10.00 लाख जो भी कम हो, देय होगी.

(ख) (1) **पेंशन के कम्युटेशन मूल्य की गणना** म. प्र. सिविल सेवा (पेंशन का कम्युटेशन) नियम, 1996 के नियम 8 के तहत जिसे मण्डल द्वारा आदेश क्र. 01-13-3395-13, दिनांक 9 मार्च 2001 से ग्राह्य किया है, के अनुसार की जावेगी.

(2) यदि किसी पेंशनर ने अपनी पेंशन का कोई भाग कम्यूट कराया है तो उसे पूर्व में प्राधिकृत कम्यूटेड मूल्य तथा पुनरीक्षित पेंशन के कारण कम्यूटेड मूल्य के बीच के अन्तर का भुगतान प्रदान नहीं किया जावेगा.

- (ग) अर्जित अवकाश नगदीकरण के लिए मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड पे) तथा इस पर देय मंहगाई भत्ते को मासिक उपलब्धियां माना जाएगा. अर्जित अवकाश नगदीकरण की पात्रता तथा शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी.
- (5) दिनांक 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि के बीच सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन, पुनरीक्षित वेतनमान में काल्पनिक तौर पर निर्धारित की जाकर वास्तविक भुगतान 1 सितम्बर 2008 (माह सितम्बर 2008 की पेंशन जो 1 अक्टूबर 2008 को देय होगी) से देय होगा.
- (6) इन निर्देशों के अन्तर्गत समेकित पेंशन/परिवार पेंशन, मूल पेंशन होगी. दिनांक 1 सितम्बर 2008 की पेंशन (माह सितम्बर 2008 की पेंशन जो 1 अक्टूबर 2008 को देय) से मूल पेंशन पर 12 प्रतिशत की दर से तथा माह जुलाई 2009 (माह जुलाई 2009 की पेंशन जो माह अगस्त 2009 में देय) से 16 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत देय होगी. उपरोक्त पैरा 3 अनुसार वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी. मंहगाई

राहत देने के संबंध में अन्य शर्तें पूर्व में प्रसारित मंहगाई राहत के आदेशों के अनुसार होगी.

- (7) दिनांक 1 सितम्बर 2008 से 31 जुलाई 2009 के मध्य सेवानिवृत्त/दिवंगत हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को, ग्रेज्युटी एवं अर्जित अवकाश नगदीकरण की अंतर राशि का भुगतान 6 (छः) समान मासिक किश्तों में किया जावेगा.
- (8) पेंशन तथा परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया अंतर राशि का भुगतान भी 6 (छः) समान मासिक किश्तों में किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2009

क्र. 01-13-3251-17.—मण्डल के आदेश क्रमांक 01-13-3251-11, दिनांक 13 अगस्त 2009 के तारतम्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण, संबंधित लेखा इकाई द्वारा किया जावेगा.

आदेशानुसार,

संतोष तिवारी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कार्मिक)

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 17 फरवरी 2010

क्र. 401-मण्डी निर्वाचन-10.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), कृषि उपज मण्डी समिति, बालाघाट के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नाम-निर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र. (1)	मण्डी समिति का नाम (2)	नाम-निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (3)	प्रतिनिधि (4)	मण्डी अधिनियम की धारा (5)
1	बालाघाट	श्री अतुल कुमार वैद्य, मु.पो. हट्टा	विधायक परसवाड़ा	11(1) (घ)
2	— " —	श्री धनीराम कावरे पिता श्री बिरजलाल कावरे वार्ड नं. 31 सरेखा (बालाघाट)	तुलैया/हमाल	11(1) (छ)

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्र. क्यू-2-ख-स्था.-6-17-दो-2009.—श्री अनिल व्यास, डिप्टी कलेक्टर, ग्वालियर को कार्यालयीन आदेश क्रमांक क्यू-2-ख-स्था-6-17-बत्तीस-07, दिनांक 31 दिसम्बर 2009 द्वारा मध्यप्रदेश, लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 की धारा 3, ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी का कार्य सौंपा गया है.

2. अतः मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-1-40-87-2-ए(3), दिनांक 10 जुलाई 1987 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रकाश में श्री अनिल व्यास, डिप्टी कलेक्टर, ग्वालियर को मध्यप्रदेश लोक परिसर अधिनियम 1974 की धारा 3 के अन्तर्गत ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा नियुक्त किया जाता है.

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर.

## कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र. भवन-2010-2809.—मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 097-1197-08-सत्रह-मेडि-3, भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2010 के द्वारा राज्य शासन एतद्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. 4336, दिनांक 16 मई 2008 के अनुपालन में सामु. स्वा. केन्द्र, ब्यौहारी का नाम परिवर्तन कर अब स्व. श्री लवकेश सिंह, सामु. स्वा. केन्द्र, ब्यौहारी रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतः खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामु. स्वा. केन्द्र, ब्यौहारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश को आदेशित किया जाता है कि भविष्य में पत्राचार करते समय स्व. श्री लवकेश सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्यौहारी लिखा जावे साथ ही सामु. स्वा. केन्द्र के स्थान पर स्व. श्री लवकेश सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्यौहारी के नाम का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें.

डॉ. टी. एन. चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.

## मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,

प्लॉट नं. 76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. 301-001-2004.—मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 5-4-2004-29-2, दिनांक 28 जनवरी 2004 एवं माननीय चयन समिति की बैठक दिनांक 13 अक्टूबर 2009 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम-विदिशा अपने वर्तमान प्रभार के साथ-साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम-रायसेन में आवश्यकतानुसार आयोजित बैठकों में अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम-रायसेन/विदिशा के साथ भाग लेकर प्रकरणों की सुनवाई करेंगी. यह व्यवस्था जिला उपभोक्ता फोरम-रायसेन में सदस्य की नियुक्ति अथवा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के आदेशानुसार,  
महेश प्रसाद अवस्थी, रजिस्ट्रार.



## राज्य शासन के आदेश

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2010

क्र. 1-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा अर्जित रकबा		
			क्रमांक (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया	बागसी	332/1 0.206	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	बागसी जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1-अ-82-2009-10-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा अर्जित रकबा		
			क्रमांक (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया	बिरहा श्यामखेड़ी	258/2/2 0.060	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	बिरहई जलाशय के बांध एवं स्पिल चैनल के निर्माण कार्य हेतु.
			258 0.203		
			5/क/2		
			258 0.202		
			5/क/3		
			340 0.809		
			367/166 0.049		
भोपाल	बैरसिया	पिपलिया हसनाबाद	योग . . 1.323		
			104/1 0.729		
			योग : 0.729		
			कुल योग : 2.052		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिवशेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

राजगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. 1126-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	देवलीकलां	1.722	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजगढ़.	रावतपुरा तालाब की शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु शेष भूमि का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	रावतपुरा	0.563		
			कुल योग : 2.285		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

अशोकनगर, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. क्यू-भू-अर्जन-105-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुका	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	ईसागढ़	बरौदिया	31.758	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर, म.प्र.	पचलाना बांध का निर्माण कार्य

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गीता मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्र.क्र. 04 अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	सगौनी	91.90	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	सगौनी जलाशय योजना डूब, बांध क्षेत्र के प्रयोजन में आने वाली भूमि.
योग : 91.90					

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—सगौनी जलाशय योजना डूब, बांध क्षेत्र के प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र.क्र. 7 अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की

धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	फतेहपुर	41.22	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	फतेहपुर जलाशय योजना के प्रयोजन में आने वाली भूमि.
		देवदरा	20.04		
		योग :	61.26		

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—फतेहपुर जलाशय योजना के प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र.क्र. 8 अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	सुनेरा	3.29	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	वराना जलाशय योजना के प्रयोजन में आने वाली भूमि.
		दमोतीपुरा	1.46		
		योग :	4.75		

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—वराना जलाशय योजना के प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

प्र.क्र. 9 अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	कनौराकलां	97.34	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	कनौरा जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल के प्रयोजन में आने वाली भूमि.
योग : 97.34					

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—कनौरा जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. ए. खण्डेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 18 फरवरी 2010

प्र.क्र. 02-अ-82-2007-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—सिरोंज

(ग) ग्राम—अहमदाबाद खिल्ली, भौरिया, सिद्धीकपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.557 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा  
(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम—अहमदाबाद खिल्ली

79/1	0.139
79/2	0.026
83	0.039
84/2	0.026
86	0.039
87/4	0.026
81	0.570
88	0.316
89	0.026
93	0.139
94/1	0.165
94/2	0.078
94/3	0.038
98	0.103
99	0.092
100	0.078
120	0.065
121	0.114
122	0.039
123	0.365
124/1	0.185
124/2	0.227
129	0.078
130/1	0.026
130/2	0.052
133/2	0.039
137/3	0.065
143/3	0.050

(1)

(2)

144/1	0.113
149	0.039
161	0.039
162/1	0.114
163	0.078
384/1	0.139
384/2	0.114
392	0.026
393	0.200
418	0.065
419	0.091
420	0.139
422	0.152
431/1	0.078
431/2	0.078
433/2	0.065
434	0.013
435	0.139
436/4	0.065
436/5	0.115
437/2	0.093
438/2	0.093

ग्राम—भौरिया

31	0.036
127	0.126
42/1	0.091
39	0.026
37	0.114
41	0.013
126	0.029
33/1	0.065
33/2	0.105
36/1	0.139
36/2	0.114
35	0.126
32	0.114

ग्राम—सिद्धीकपुर

7	0.032
8	0.070
11/1	0.026
11/2	0.078

योग . . 6.557

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम अहमदाबाद खिल्ली, तहसील सिरोंज लघु सिंचाई योजना की नहर में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बावत्.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज व कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2010

क्र. 12-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) नगर/ग्राम—कालापीपल, कोल्हूखेड़ी, कढ़ैयाखुर्द,  
बड़ली जागीर, बागसी, भाऊपुरा, बिजावन खुर्द.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—270.975 हेक्टर.

खसरा नं.

लगभग क्षेत्रफल  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

ग्राम-कालापीपल

3/3

1.051

3/6

0.809

3/7

1.590

3/8

1.800

9

0.202

10

0.809

11

0.980

12/2

0.332

12/3

0.485

12/4

0.081

12/5

0.465

12/9

0.708

28/2/क

0.060

30/1

0.443

30/2/ख

0.040

30/2

0.052

30/3

0.052

30/4

0.053

31

0.409

32/1

0.077

32/2

0.077

(1)

(2)

32/3

0.077

32/4

0.077

32/5

0.303

34/1

0.041

34/2

0.238

35/1

0.049

35/2

0.049

35/3

0.049

35/4

0.049

35/5

0.048

35/6

0.170

36/1

0.361

36/2

0.052

36/3

0.065

37

0.360

38

0.077

39/1

0.141

39/2

0.190

39/3

0.194

39/4

0.194

39/5

0.020

39/6

0.405

39/9

0.101

42

0.198

43

0.486

44

0.271

45

0.320

53/2

0.140

53/5

0.105

53/6

0.850

53/7

0.547

53/8

0.567

53/12

0.370

54/1

0.809

55

0.894

56/1

0.323

56/4

1.601

56/5

0.260

56/6

0.351

56/7

0.101

56/8

0.283

56/9

0.303

56/10

0.162

56/11

0.607

(1)	(2)	(1)	(2)
56/12	0.050	7/1/2/1/1	1.530
56/13	0.607	7/1/3/1	0.992
56/14	0.607	7/1/3/1/2	1.011
56/15	0.506	11	0.174
56/16	1.315	12	0.255
56/17	0.283	13/2	0.141
57/1	0.870	14/2	1.600
57/2	0.858	15	0.050
57/3	1.728	16/1	0.162
57/4	1.728	16/2	0.045
58	2.776	23/1	0.182
59/1	0.409	23/2	0.360
59/2	0.555	23/3	0.252
59/3	0.600	23/4	0.136
59/4	0.728	23/5	0.131
59/5	0.728	23/6/1	0.136
59/6	0.745	23/6/2	0.131
59/7	0.745	23/7	0.135
60/1	0.048	53	0.324
60/2	0.049	63/1/1	0.324
60/3	0.065	63/1/2	0.405
62	2.023	63/2	0.283
63/2/1	0.405	63/3	0.264
63/2/2	0.405	64/1	0.445
63/2/3/2	2.023	81/1/1	1.415
63/2/4	0.405	87/1	0.668
63/2/5	1.619	87/2	0.250
योग . .	46.313	95, 96, 97, 16,	
ग्राम-कोल्हूखेड़ी		3, 164, 166/2	0.405
		167, 168/1	
4/2/3	0.101	95, 96, 97, 16,	
7/4	0.160	3, 164, 166/2,	0.283
7/7	0.060	167, 168/2	
7/5	0.024	170/1	0.164
7/8	0.350	170/2	0.174
7/11	0.307	172/1	0.077
7/12	0.110	172/2	0.081
7/2/6	0.688	173/2	0.020
7/2/7	0.627	174	0.413
7/2/8	0.600	175/2	0.056
7/2/9	0.607	181/1	0.065
7/2/10	0.607	182	1.345
7/2/11	0.688	183	0.060
7/1/2	1.011	187/1	0.250
		187/2	0.101



(1)	(2)	(1)	(2)
188/1	0.065	249	0.057
188/2	0.129	250	0.105
189/1/1/1	0.101	251	0.190
189/1/1/2	0.607	252	0.105
191	0.117	254	0.109
192	0.239	257	0.045
194/1	0.085	263	0.668
194/2	0.085	264	1.130
195, 196/2	0.065	265	0.324
197/1	1.287	266	0.210
197/2	0.121	267/1	0.882
200, 202/1	0.607	267/2, 600/266	0.409
201/1	0.066	267/3	0.405
203	0.032	270	0.032
204	0.113	272	0.077
205	0.028	274	0.041
206	0.101	275	0.121
207/1	0.073	277	0.061
207/2	0.069	279	0.032
209	0.097	285	0.089
210	0.218	286	0.105
211	0.133	287	0.012
214/1	0.227	288	0.057
214/2	0.040	290	0.129
215	0.073	293	0.186
216	0.089	294, 295	0.121
217	0.045	335/1	0.162
218	0.109	335/2, 602/335/2, 603/335,	0.527
219	0.057	655/335/2, 655/335/3	
220	0.012	337/1	0.421
221/1	0.024	337/2, 337/4	0.381
221/2	0.028	340/1	3.363
222	0.012	340/2, 342	0.850
224	0.024	343	1.100
223/624/261	0.073	340/3, 341	0.202
225	0.020	345, 346	0.060
227	0.069	347, 348, 384/2	3.480
230	0.186	349, 350, 351, 360	7.482
232	0.251	352	2.282
233, 235	0.251	354	6.637
241	0.020	356	1.607
245	0.154	358	2.201
246	0.105	359	0.295
247	0.202	360	2.485

(1)	(2)	(1)	(2)
363	0.299	409, 411	1.708
364	0.575	410	0.150
365, 366	2.566	412, 413/1क	0.384
374/1/1/3	2.833	299	0.020
374/3	0.182	300	0.060
375/1	0.355	302	0.207
375/2	0.354	307/1	0.538
377/1/1/1	2.023	310, 331/6/1क	0.101
377/1/1/2	2.023	606/416	0.405
377/1/1/3	2.023	416/2	0.202
377/1/1/4	2.023	418	0.550
377/1/2	2.023	419/1/1क	0.405
377/1/3	5.370	419/1/1ख	1.092
377/2, 378/382/2/2/क	0.405	419/1/2	1.940
377/2, 378/382/2/5/ख/1	0.202	419/2	0.809
377/2, 378/382/2/3/ग	3.237	421/1/1/2	0.970
377/2, 378/382/2/2/1घ	0.060	421/1/1/3	0.607
377/2, 378/382/2/2/2घ	0.405	421/1/1/4	4.250
377/2, 378/382/2/2/3घ	0.060	421/1/1/5	1.780
377/2, 378/382/2/4/1ङ	0.180	421/1/1/6	1.740
377/2, 378/382/2/4/2ङ	1.210	421/1/1/7	0.303
379, 381/1	1.011	421/1/1/8	1.255
379, 381/2	2.722	421/1/1/9	1.780
385/1/1/2	0.619	421/1/2	0.486
385/1/2	2.023	421/2	0.081
385/2, 387/1	3.845	421/3	0.405
387/2/2	0.542	423/1	0.445
388	0.308	423/2	0.405
389	0.825	426	0.350
390	0.227	427/2	0.360
391	0.077	449/1	1.255
394	0.040	449/2	3.147
398	0.050	450/1/2	1.113
399/2	2.023	450/1/1/1/1	0.081
399/1	2.100	450/2	0.045
400	0.670	455/1	0.089
401	0.227	367	0.073
402, 403/1, 405/1,	0.425	368	2.501
403/2, 405/2		372, 374/2, 374/4	1.210
404	0.486	374/1/1/1	4.047
406	0.182	374/1/1/2	2.023

(1)	(2)	(1)	(2)
466	0.202	597/187	0.230
467	0.283	604/401	0.145
458	0.202	611/419	2.940
470, 471	0.405	614/448/2	0.065
472	0.242	618/578	0.615
473	0.036	623/202/2	0.085
474	0.016	625/202/2	0.202
477	0.141	629/588/355/1	1.400
482/1/1	0.105	629/588/355/2	2.023
482/1/2	0.162	636/187	0.121
482/3	2.023	637/187	0.162
490	0.405	642/289	0.012
495	0.603	645/289	0.008
496	0.194	647/289	0.004
497	0.285	648/289	0.008
498	0.364	653/95	0.202
499	1.267	656/412	3.070
501/1	1.708	619/578	0.930
501/2	0.202	412, 413/1ख	0.101
502	0.101	412, 413/2	0.121
503/1	0.360	412, 413/3/1क	0.020
504	0.242	414	0.060
503/2	0.040	416/1	0.020
505/2	0.405	योग . .	196.691
505/4	0.567		
505/5	0.905	ग्राम-कढ़ैयाखुर्द	
505/6	0.770		
507/2	0.825	75	0.028
380/1	0.081	76	0.239
380/2	1.659	78	0.020
384/1/1	2.023	81	0.081
384/1/2	5.678	82	0.214
385/1/1/1	0.360	83	0.020
517/1	0.930	84	0.121
519/1/1	0.585	85	0.154
519/1/2	0.603	86	0.405
519/2	1.853	87	0.878
585/459	0.817	88	0.214
589/338/2	2.833	93	0.040
590/355	0.328	96	0.190
591/355, 592/355	0.174	97	0.210

(1)	(2)	(1)	(2)
98	0.040	93/14/1/1	0.262
99	0.198	93/14/1/2	0.060
100	0.093	योग . .	7.048
101	0.247	<b>ग्राम-बागसी</b>	
102	0.332		
103	0.445	371/1क	0.081
104	0.162	371/1ख	1.133
106	0.089	371/2	0.405
107	0.016	371/3	1.570
108/2	2.850	371/4/1	1.972
124/108	0.243	371/4/2	0.728
126/83	0.045	372/1/1/2	0.546
128/86	0.567	372/1/1/3	1.295
129/108	0.131	372/1/2	0.478
130/96	0.053	379/1	0.405
131/96	0.045	379/3	0.283
132/96	0.040	योग . .	8.896
133/99	0.089	<b>ग्राम-भाऊपुरा</b>	
134/100	0.093	149/2	0.708
139/96	0.886	150, 153	0.506
140/88	0.405	योग . .	1.214
योग . .	9.883	<b>ग्राम-बिजावनखुर्द</b>	
<b>ग्राम-बड़ली जागीर</b>		201	0.300
5, 6/1	0.165	203	0.120
5, 6/2	0.287	204	0.010
9	1.360	205	0.030
10/1	0.712	206	0.030
10/2	0.445	207	0.120
12/1	0.405	208	0.320
12/2क	0.141	योग . .	0.930
12/2ख	0.081	महायोग . .	270.975
22/1	0.247	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कालापौल जलाशय के बांध एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु.	
22/2	0.247	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
89/10/2	0.688	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
89/10/3	1.050	शिवशेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
89/10/4	0.262		
89/10/5	0.085		
89/10/6	0.101		
92/5/1	0.450		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र. 1460-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा  
(ग) नगर/ग्राम—भूतेरा, प.ह.नं. 31, ब. नं. 435,  
रा.नि. मंडल-छिन्दवाड़ा.

- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—16.591 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेर में) (2)
611/3	0.692
627/1	01.072
628/1	01.080
611/2	0.608
627/2	01.072
623	01.428
622/5	01.013
625/1	02.509
622/4	0.820
626/1	01.107
626/2	0.707
626/3	0.707
628/2	01.081
629	0.105
636/1	0.095
641/1	0.094

(1)

(2)

641/2	0.050
636/2	0.060
641/3	0.100
641/4	0.100
642/1	0.028
644	0.206
632, 633	0.049
645	0.093
646	0.129
647	0.162
568/1	0.090
567	0.040
308/1	01.000
342/3	0.169
619	कुंआ पक्का-01
606/2	कुंआ पक्का-01
608/2	कुंआ पक्का-01
643	0.125
615/1	कुंआ कच्चा-01
548	कुंआ पक्का-01

योग . . 16.591 हेक्टेर

एवं प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर आने  
वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, संभाग-चौरई के उप संभाग चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र. -दस-भू-अर्जन-फा-510-प्र.क्र.4-अ-82-2008-09-665.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल  
(ख) तहसील—सोहागपुर  
(ग) नगर/ग्राम—चंदनिया बड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.409 हेक्टर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
135	1.440
140	0.405
143	0.175
138	0.179
142	0.210
योग . .	2.409

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बंधवा जलाशय के स्पिल चैनल एवं डैमशीट निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-359.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर  
(ख) तहसील—कालापीपल  
(ग) ग्राम—रामडी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.645 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टर में) (2)
10	0.147
227/2	0.157
14	1.129
41/3	0.209
43	0.105
44	0.120
45/1	0.073
263/1	1.212
46	0.040
51/2	0.021
52/2	0.118
53	0.094
55/3	0.063
54	0.010
217	0.240
218/2	0.084
221/1	0.199
222/1	0.105
223/1	0.219
224/7	0.387
248/2/3	0.104
248/2/4	0.105
248/2/5	0.105
248/4	0.282
249/1	0.014
249/2	0.013
249/3	0.013
250/1/1	0.414
250/1/3	0.265

(1)	(2)	(ग) लगभगक्षेत्रफल—5.299 हेक्टेयर.
252/1	0.063	एल.बी.सी नहर :
252/2	0.366	सर्वे नं.
275/1	0.732	रकबा
276/2	0.690	(हेक्टेयर में)
277/2	0.324	(1)
278/1	0.157	(2)
278/2	0.157	ग्राम—खारपुरस, क्षेत्रफल 1.701 हेक्टेयर
283	0.533	101/6
285/1	0.576	102/2
		102/1
		128
		129
		125/157/2
		130
		121
		93
		111
		81
		80
		65
		69/1/3
		69/1/5
		11/6
		11/8/1
		11/1
		18/2
		18/3
		18/4
		27

कुल योग . . 9.645

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरदौनकलाँ उगली-शुजालपुर मार्ग हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),  
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. 1128-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बाजपुरा एल.बी.सी.एवं आर.बी.सी. नहर निर्माण कार्य) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़ के ग्राम

ग्राम—लावाबे, क्षेत्रफल 0.606 हेक्टेयर

269	0.058
270	0.058
283/3	0.106
293/1/9	0.128
293/1/4	0.128
293/1/3	0.128

ग्राम—पाटरीखुर्द, क्षेत्रफल 0.898 हेक्टेयर

171	0.058
173	0.034
174	0.097
169	0.180
158/2	0.160
161	0.067
159	0.078

(1)	(2)
160/2/3	0.078
144	0.032
145/3	0.064
143	0.050

ग्राम—खारपुरस, क्षेत्रफल 0.376 हेक्टेयर

94	0.052
93	0.180
57/4	0.050
57/1/8	0.094

ग्राम—भवानीपुरा, क्षेत्रफल 1.642 हेक्टेयर

99	0.090
97/1	0.020
91	0.234
90/1	0.024
90/2	0.024
90/3	0.024
90/133/1	0.024
90/133/2	0.024
90/133/3	0.024
89/132/1	0.041
89/132/2	0.041
86/2	0.260
82/4	0.068
82/5	0.070
49	0.908

ग्राम—बाजपुरा, क्षेत्रफल 0.076 हेक्टेयर

55	0.076
----	-------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बारपुरा एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. नहर कार्य निर्माण हेतु भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, 24 फरवरी 2010

क्र. क्यू-भू-अर्जन-340-2009-10.—चूँकि, राज्य शासन को

समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के वर्ग (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर  
(ख) तहसील—अशोकनगर  
(ग) ग्राम—सेपरा, पटवारी हल्का नं. 34  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.207 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
360/2	0.089
361	0.219
362	0.343
366/1ख	0.302
368/3ग	0.254
योग	1.207

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सोवत स्टापडेम कमकाजवे पहुंच मार्ग निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गीता मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्र.क्र 234-82-वर्ष. 2008-2009.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक



प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—हटा

(ग) नगर/ग्राम—(1) डौली, पटवारी हल्का नंबर 09

(2) तिगरा, पटवारी हल्का नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.87 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
<b>ग्राम—डौली की भूमि</b>	
4 में से	0.08
73 में से	0.07
72 में से	0.01
74 में से	0.04
75/3 में से	0.13
75/1 में से	0.16
75/2 में से	0.05
92 में से	0.08
94 में से	0.11
95 में से	0.04
96 में से	0.05
115 में से	0.06
328 में से	0.16
329 में से	0.01
327/1	0.06
327/2 में से	0.07
326 में से	0.06
303 में से	0.03
75/1 में से	0.04
75/3 में से	0.04
88 में से	0.07
86 में से	0.07
85 में से	0.07
105/1 में से	0.07

#### ग्राम—तिगरा की भूमि

56/2 में से	0.10
113 में से	0.09

(1) (2)

120 में से	0.15
123 में से	0.07
124 में से	0.12
125 में से	0.13
128 में से	0.08
129 में से	0.18
130 में से	0.10
344 में से	0.14
345 में से	0.08

योग . . 2.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—समधन जलाशय योजना की नहर में आने वाली भूमि में निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वे संभाग, हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. ए. खंडेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 1 अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) नगर/ग्राम—जलकुंआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.05 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
190/1 पैकी	0.02
190/4 पैकी	0.07
190/2 पैकी	0.08
190/3 पैकी	0.11
194 पैकी	0.01
195 पैकी	0.14
197/1 पैकी	0.30
198/1 पैकी	0.04
210 पैकी	0.17
225 पैकी	0.04
226/1 पैकी	0.49
226/2 पैकी	0.43
234 पैकी	0.93
235 पैकी	0.27
249 पैकी	0.01
250/1 पैकी	0.50
250/2 पैकी	0.40
253/2 पैकी	0.32
277/4 पैकी	0.03
278/5	0.30
282/1 पैकी	0.31
282/2 पैकी	0.27
282/3 पैकी	0.12
253/1 पैकी	0.01
278/2 पैकी	0.34
278/3 पैकी	0.34
योग . .	<u>6.05</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक-दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,

1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) नगर/ग्राम—पुरनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.44 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
226/2ख पैकी	0.03
738 पैकी	0.20
740/1 पैकी	0.21
740/2	0.06
741/2 पैकी	0.25
741/3 पैकी	0.20
741/4 पैकी	0.11
741/5 पैकी	0.13
746/2 पैकी	0.60
747 पैकी	0.33
748/1 पैकी	0.05
748/2 पैकी	0.09
748/3 पैकी	0.15
752/3 पैकी	0.13
752/4 पैकी	0.52
752/6 पैकी	0.08
761/1 पैकी	0.15
761/2 पैकी	0.19
761/1/3 पैकी	0.20
761/4 पैकी	0.25
761/5 पैकी	0.03
762 पैकी	0.45
763 पैकी	0.03
योग . .	<u>4.44</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक-दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पुनासा  
(ग) नगर/ग्राम—बिजौरामाफी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.00 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
129 पैकी	0.07
130/2 पैकी	0.61
131 पैकी	0.36
152 पैकी	0.46
153 पैकी	1.17
155/1 पैकी	0.20
152/2 पैकी	0.06
164 पैकी	0.29
166 पैकी	0.02
171/1 पैकी	0.14
180/1 पैकी	0.13
171/2 पैकी	0.55
172/1 पैकी	0.10
172/2 पैकी	0.20
173/1 पैकी	0.06
172/3 पैकी	0.27
172/4 पैकी	0.28
228 पैकी	1.03
योग . .	<u>6.00</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक-दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 05-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पुनासा  
(ग) नगर/ग्राम—दिनकरपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.60 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
101/2 पैकी	0.35
167/1 पैकी	0.30
169 पैकी	0.02
170 पैकी	0.30
173 पैकी	0.31
182 पैकी	0.11
184 पैकी	0.54
185 पैकी	0.09
239/1 पैकी	0.30
239/2 पैकी	0.25
240 पैकी	0.01
242 पैकी	0.16
243 पैकी	0.65
246 पैकी	0.19
247 पैकी	0.08
250 पैकी	0.34
252 पैकी	0.07
253 पैकी	0.02
313 पैकी	0.06
321/2 पैकी	0.37
321/4 पैकी	0.08
योग . .	<u>4.60</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी से पावर हाउस तक पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक-दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 06-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पुनासा  
(ग) नगर/ग्राम—देवला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.21 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
129 पैकी	0.10
131 पैकी	0.55
156/1 पैकी	0.27
156/2 पैकी	0.09
156/3 पैकी	0.02
156/4 पैकी	0.06
176 पैकी	0.19
179 पैकी	0.02
180 पैकी	0.01
203 पैकी	0.81
260 पैकी	0.40
272 पैकी	0.10
273/1 पैकी	0.39
273/2 पैकी	0.22
273/3 पैकी	0.20
280 पैकी	0.72
282 पैकी	0.06
योग . .	<u>4.21</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी से पावर हाऊस तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक-दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी.डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्र. क्र. 7-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर  
(ख) तहसील—गौरिहार  
(ग) ग्राम—नीबीखेड़ा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—6.895 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
69	0.141
70	0.024
71/1	0.202
78	0.012
80	0.261
81	0.112
82	0.008
84/1	0.051
85	0.130
87/2	0.016
88	0.041
116	0.008
117	0.008
121	0.008
122	0.243
123	0.095
124	0.048
125	0.252
126	0.051
149	0.414
150/2	0.042
152/2	0.093
152/3	0.050

(1)	(2)	(ग) ग्राम—खड़ेही	
152/4	0.178	(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.222 हेक्टर.	
153	0.012		
158	0.344	खसरा	अर्जित रकबा
159	0.396	नम्बर	(हेक्टर में)
702/1	0.372	(1)	(2)
702/2	0.044	295/1	0.185
1084/1	0.125	295/2	0.063
1084/2	0.051	296	0.115
1086	0.224	297	0.162
1088	0.340	298	0.020
1089	0.048	299	0.048
1092	0.081	307	0.384
1093	0.156	311	0.040
1094	0.161	312	0.081
1095	0.461	313	0.089
1096	0.296	314	0.024
1099/1/1	0.031	444	0.048
1099/1/2	0.193	445	0.072
1099/2/1/1	0.112	446	0.161
1099/2/1/2	0.134	448/1	0.158
1099/2/2	0.202	448/2	0.010
1101	0.016	449	0.096
1114	0.036	452/1	0.010
1119	0.048	452/2	0.232
1144	0.328	453	0.036
1145	0.196	456	0.008
योग . .	6.895	460	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंडी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर  
(ख) तहसील—गौरिहार

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंडी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 फरवरी 2010

भू-अर्जन-463-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—पड़रा (शान्ति बिहार कालोनी से लगी हुई)
- (घ) क्षेत्रफल—0.650 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित हेतु प्रस्तावित (रकबा हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96/1	0.227
96/2	0.085
98/1	0.018
98/2	0.018
99	0.073
100	0.069
103	0.160

योग . . . 0.650

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—एम.पी. हाउसिंग बोर्ड के अन्तर्गत निर्मित शान्ति बिहार कालोनी की जल निकासी एवं आवासीय योजना का निर्माण कार्य.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष 2006-2007.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—पवई
- (ग) ग्राम—रामनगर
- (घ) क्षेत्रफल—0.410 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित (रकबा हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
18	0.16	निजी भूमि
19	0.10	निजी भूमि
22/1	0.03	निजी भूमि
30	0.08	निजी भूमि
28	0.04	निजी भूमि

योग . . . 0.410

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मुडवारी उद्भवहन सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 2 मार्च 2010

क्र. 2520-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धार  
(ग) ग्राम—महाराजखेड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.444 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
331/1	0.222
331/2/1	0.184
331/2/2	0.025
331/3	0.155
331/4	0.178
334	0.062
338	0.140
343	0.095
346	0.267
339/1	0.098
347/1	0.018
योग . .	1.444

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, इन्दौर

(म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2525-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धार  
(ग) ग्राम—आबुखेड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.118 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
24/1	0.284
24/2	0.497
25/2	0.070
26/1	0.012
26/2	0.215
26/3	0.040
योग . .	1.118

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, इन्दौर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2530-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धार  
(ग) ग्राम—कलसाड़ा खुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.763 हेक्टर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
279/1	0.035
279/2ख/1/1/1	0.016
279/2ख/1/1/2	0.229
279/2ख/1/2	0.231
279/2क/2	0.253
279/2क/4	0.479
279/2ग/1	0.201
285/1	0.622
287	0.073
288	0.659
289/2	0.218
323	0.806
329/2	0.770
331	0.587
332/1	1.026
343/7	0.132
343/8	0.008
398/1	0.092
404/1	0.403
406	0.313
407	0.456
408	0.076
409	0.077
410	0.196
411	0.085
412	0.288

(1)	(2)
413	0.153
415	0.082
416	0.128
417	0.134
418	0.935

योग . . 9.763

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, इन्दौर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2535-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—धार  
(ग) ग्राम—एकलदूना (दिगठान)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.567 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.125
4/1	0.438
18/1	0.560
20/1	0.235



(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
20/2	0.132	
24/1	0.043	
55/1	0.002	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, इन्दौर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
57	0.102	
65	0.295	
70/1	0.175	
70/2	0.175	
71	0.215	क्र. 2561-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—
73/1/1	0.005	
73/3/2	0.060	
74/1	0.220	
74/2	0.430	
83/2	0.380	
85/2	0.737	
152/1	0.650	अनुसूची
152/2	0.030	(1) भूमि का वर्णन—
153	0.490	(क) जिला—धार
154	0.450	(ख) तहसील—धार
155	0.051	(ग) ग्राम—लेबड़
157	0.150	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.155 हेक्टर
158/1/2	0.150	सर्वे नम्बर
158/1/4	0.310	अर्जित रकबा
159/2/1	0.580	(हेक्टर में)
175	0.190	(1) (2)
176/1	0.340	253/3 0.459
180/1	0.320	253/4 0.567
180/2	0.240	254/1 0.129
182	0.380	योग . . 1.155
183	0.220	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.
184	0.320	
186/1	0.440	
186/2/1	0.065	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, इन्दौर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
186/2/2	0.250	
187	0.382	
188	0.230	

योग . . 10.567

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर  
जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2010

क्र. 194-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-ए).—नव नियुक्त, नौ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय चरण की कार्यशाला "Foundation Course Training Programme", जो दिनांक 08-03-2010 से 20-03-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 08-03-2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होगी :-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन-पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 08-03-2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे, महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंगे।
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके द्वारा पारित/विरचित किये गये निम्न की एक प्रति प्रशिक्षण प्रारंभ होने से यथासंभव पूर्व संस्थान को आवश्यक रूप से भेजें:-
  - (1) सत्र प्रकरण का निर्णय जिसमें साक्षी पक्ष द्रोही न हुआ हो,
  - (2) व्यवहार वाद (अ) का निर्णय,
  - (3) व्यवहार वाद अपील (अ) का निर्णय,
  - (4) आपराधिक अपील/पुनरीक्षण का निर्णय,
  - (5) 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित अभियुक्त का बयान,
  - (6) वाद विषय ( Issues)
  - (7) आरोप ( Charges)

5. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं।
6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन या बस स्टैण्ड पर टैम्पो ट्रेक्स की व्यवस्था की जावेगी। अतः न्यायिक अधिकारी, जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679, पर समयावधि रहते सूचित करें।
8. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारी के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे।
9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
जयन्त चव्हाण, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 24<sup>th</sup> February 2010

No. D-844-II-15-50-87-V.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Sub-Section (2) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (59 of 1994), read with sub-regulation 2 of the Regulation 3 of Madhya Pradesh Legal Services Authorities Regulations, 1997 as amended under section 29 A of M.P. State Legal Services authority Act, 1987, Hon'ble the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, nominates Hon'ble Shri Justice S.L.Kochar, High Court of Madhya Pradesh, Bench Indore, as Co-Chairman of High Court Legal Services committee at Indore, with immediate effect.

No. D-846-II-15-50-87-V.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Sub-Section (2) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (59 of 1994), read with sub-regulation 2 of the Regulation 3 of Madhya Pradesh Legal

Services Authorities Regulations, 1997 as amended under section 29 A of M.P. State Legal Services authority Act, 1987, Hon'ble the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, nominates Hon'ble Shri Justice A. K. Shrivastava High Court of Madhya Pradesh, Bench Gwalior, as Co-Chairman of High Court Legal Services Committee at Gwalior, with immediate effect.

By order and in the name of Hon'ble the Chief Justice,  
JAYANT CHAVHAN, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 25 फरवरी 2010

क्र. B-1018-दो-2-16-10.—श्री रामकुमार चौबे, ओ.एस.डी., जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2007 से दिनांक 06 नवम्बर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-1020-दो-2-53-2007.—श्री आर.के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 04 से 06 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.के.गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1022-दो-2-23-2005.—श्री ए.के. पटैरया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 02 से 05 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए.के. पटैरया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए.के. पटैरया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-877-दो-2-23-2009.—डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 30 जनवरी से 01 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डा. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-880-दो-2-23-2009.—डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 05 फरवरी से 11 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12,13 एवं दिनांक 14 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डा. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-883-दो-3-10-2006.—श्री बी.एस. परमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 25 से 27 जनवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी.एस. परमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी.एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

ए.एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.